खनन नीति से चार गुना बढ़ा राजस्व

उत्तराखंड की वर्तमान मिनरल पॉलिसी सबसे बेहतरीन

सितारगंज। उत्तराखंड के प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी एवं कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्वामी शिवकुमार अग्रवाल ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता करते हुए राज्य की खनन एवं पर्यटन नीति पर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में उनके पास 1966 से अब तक 60 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव है और उत्तराखंड में खनन क्षेत्र को लेकर हो रही आलोचनाएं तथ्यहीन हैं।

उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी एलएससी इंफराटैक लि. पिछले 35 वर्षों से उत्तराखंड में मिनरल एवं माइनिंग सेक्टर में कार्य कर रही है। यह एशिया की सबसे बड़ी मिनरल प्रोसेसिंग कंपनी है, जिसकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 10 इकाइयां तथा देशभर में कुल 16 व्यावसायिक इकाइयां संचालित हैं। कंपनी से जुड़े लगभग 2000 प्रोफेशनल पार्टनर इसके पारिवारिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है कि पिछले डेढ़ साल में खनन से सरकार को चार गुना राजस्व प्राप्त हुआ है। पहले जहां यह आय लगभग 300 करोड़ रुपये थी, वहीं अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। पहले सिस्टम की कमजोरियों के कारण मिनरल की लीकेज और चोरी होती थी, जबकि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा था। अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में करीब 400 स्टोन क्रशिंग इकाइयां संचालित हैं, जो उत्तराखंड का सबसे अधिक रोजगार

शिवकुमार अग्रवाल

देने वाला उद्योग है। इस उद्योग से लगभग 7 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। रॉयल्टी, फॉरेस्ट ट्रांजिट, जीएसटी, आयकर और आरटीओ टैक्स के माध्यम से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के तहत रॉयल्टी कलेक्शन से जुड़ने का प्रस्ताव उन्हें मिला था, लेकिन इसे अत्यंत कठिन कार्य बताते हुए उन्होंने इससे अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं खनन विभाग की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में बड़े सुधार हुए हैं, जिससे यह क्षेत्र अनऑर्गनाइज्ड से ऑर्गनाइज्ड हुआ है और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर रोक लगी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड स्टोन क्रशर उद्योग द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से कोरसैंड और एम-सैंड बनाने की तकनीक विकसित की गई है, जिसे अपनाने के लिए अन्य राज्यों ने भी उनकी कंपनी से प्रेजेंटेशन लेकर अपनी नीतियां बनाई हैं। रिफार्म के बाद मिनरल मार्केट का दायरा उत्तर प्रदेश में 150 किलोमीटर तक बढ़ गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अग्रवाल ने कहा कि खनन उद्योग से उत्पन्न होने वाला अधिकांश राजस्व राज्य के भीतर ही खर्च होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो स्टोन क्रशर 40 वर्ष पहले लगाए गए थे और अब आबादी के बीच आ गए हैं, उन्हें शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा सरकारी जमीन पर स्टोन क्रशर जोन घोषित किए जाने चाहिए।